उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास विमाग-2 संख्या:-27/VII-1/31-उद्योग/2016

देहरादन : दिनांक 25 जनवरी, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

राज्य में सार्वजनिक उपकमों / निगमों / स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्य-कलापों का प्रभावी ढंग से अनुश्रवण, उनके कार्मिकों के अधिष्ठान सम्बन्धी विषयों के समाधान, समस्त सार्वजनिक उपकर्मों/ निगर्मों / स्वायत्तशासी संस्थाओं के विभिन्न विषयों पर नीति निर्धारण करने एवं सार्वजनिक निगम / उपक्रमों /स्वायत्तशासी संस्थाओं से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर परामर्श हेतु श्री राज्यपाल औद्योगिक विकास विभाग के अन्तर्गत निम्नानसार उच्चाधिकार पाप्त समिति गतित किये जाने की सदर्घ स्त्रीकृति प्रदान करते हैं --

di ALVI	an example of the first than a first and the death of the the	। अधाग करता ह -
(1)	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
(2)	प्रमुख सिवव / सिवव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
(3)	प्रमुख सचिव/सचिव कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
(4)	प्रमुख सचिव/सचिव न्याय, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
(5)	संबंधित प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव	सदस्य
(6)	प्रमुख सचिव/सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य सचिव
(7)	निदेशक, ऑडिट, उत्तराखण्ड, द्वितीय तल, किमश्नर टैक्स भवन, मसूरी बाई पास रोड रिंग रोड़, देहरादून।	सदस्य
(8)	03 विशेषज्ञ जो वित्त/लेखा/कम्पनी मामलों की गहन जानकारी रखते	सदस्य

- 2- समिति द्वारा विमिन्न विभागों के अन्तर्गत सार्वजनिक उपक्रमों / निगमों / स्वायत्तशासी संस्थाओं के मामलों पर विचार करते समय गठित समिति के अतिरिक्त जैसा आवश्यक समझे तीन विशेषज्ञों को सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।
- समिति समिति द्वारा विभिन्न विभागों के अन्तर्गत सार्वजनिक उपक्रमों / निगमों / स्वायत्तशासी संस्थाओं के मामलों निम्नलिखित प्रकरणों पर विचार करते हुये परामर्श दिया जायेगा :--
 - (1) सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारियों का वेतन पेंशन निर्धारण, वेतन विसंगतियों एवं कार्मिक विषयों का निराकरण, सार्वजनिक उपकर्मों / निगमों / स्वायत्तशासी संस्थाओं की सेवा में विभिन्न वर्ग के आरक्षित पदों के लिये शासन की सामान्य नीति के आधार पर निर्देश / मार्गदर्शन जारी करना।
 - सार्वजनिक उपक्मों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं में गैर सरकारी निदेशकों/अध्यक्षों को अनुमन्य सुविधाओं के सबन्ध में नीति निर्धारण।
 - सार्वजनिक उद्यमों के कार्य-कलापों का अध्ययन/अनुश्रवण एवं उनकी कार्य प्रणाली में सुधार लाने हेत् निर्देश / मार्गदर्शन।
 - सार्वजनिक उपकमों / निगमों / स्वायत्तशासी संस्थाओं के मार्गदर्शन एवं निर्देश हेत सामान्य नीति निर्घारण।
 - सार्वजनिक उद्यमों की राज्य सहायता के संबंध में परामर्श एवं राज्य सहायता समिति की बैठकों का आयोजन करना।
- सार्वजनिक उद्यमों / निगमों / शासकीय विभागों के मध्य उत्पन्न विवादों के संबंध में गठित सिमित से संबंधित कार्य।

4— सार्वजनिक उपकमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के उपरोक्त प्रकरणों को सम्बन्धित निदेशक मण्डल के अनुमोदन के पश्चात संबंधित प्रशासकीय विभागीय द्वारा विभागीय संस्तुति के उपरान्त औद्योगिक विकास विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा तथा औद्योगिक विकास विभाग द्वारा समिति की बैठक आयोजित कराते हुये समिति के सम्मुख निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। समिति की संस्तुतियों के पश्चात् वित्त विभाग की सहमित के आदेश जारो किये जायेगे।

5— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या— 85/xxvII(7)/2017 दिनांक 25 जनवरी, 2017 की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

(एस० रामास्वामी) मख्य सचिव

संख्या:- 27-/VII-1/31-खद्योग/2016 तदिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रमारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

3. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन, नई दिल्ली।

4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।

5. संबंधित सार्वजनिक उपकर्मो / निगमों / स्वायत्तशासी संस्थाओं के प्रबन्ध निदेशक।

महानिदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड।

7. एन०आई०सी०

8. गार्ड फाईल।

आज्ञा सें,

(राजेन्द्र सिंह पतियाल) उप सचिव